10% EWS आरक्षण पर
SUPREME COURT का
ऐतिहासिक फैसला

EWS Reservation

2019

- SC ने नौकरियों, शिक्षा में 10% EWS आरक्षण को बरकरार रखा
- SC upholds 10% EWS reservation in jobs, education

EWS Reservation

- सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से EWS आरक्षण को सही ठहराया है।
- A 5-member Constitution Bench of the Supreme Court has upheld the EWS reservation by a majority of 3-2.

EWS Reservation

The Supreme Court bench

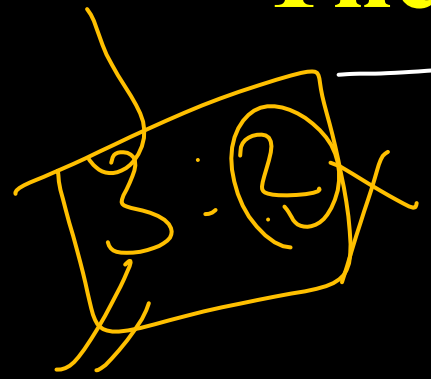

1. Chief Justice of India Uday Umesh Lalit
2. Dinesh Maheshwari,
3. S Ravindra Bhatt,
4. Bela M Trivedi,
5. J B Pardiwala

EWS Reservation

- न्यायमूर्ति माहेश्वरी: ईडब्ल्यूएस कोटा कानून आर्थिक मानदंड को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे या समानता संहिता का उल्लंघन नहीं करता है। EWS कोटा के लिए 50% से अधिक सीलिंग द्वारा किसी भी आवश्यक सुविधा को नुकसान नहीं पहुंचाता है क्योंकि सीलिंग स्वयं लचीली है।
- Justice Maheshwari: EWS quota law doesn't violate basic structure or equality code for taking into account economic criterion. It doesn't also cause damage to any essential feature by exceeding 50% ceiling for EWS quota since the ceiling is itself flexible.

EWS Reservation

- जस्टिस त्रिवेदी: ईडब्ल्यूएस कोटा कानून भेदभावपूर्ण नहीं है, इसे चौंकाने वाला नहीं कहा जा सकता। यह बुनियादी ढांचे या समानता कोड का उल्लंघन नहीं करता है और ईडब्ल्यूएस को अलग वर्ग मानना एक उचित वर्गीकरण होगा। जैसे असमान के समान समान, असमान के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता।

Art 15(6)

Art 15(4)

- Justice Trivedi: EWS quota law isn't discriminatory, can't be said to be shocking. It doesn't violate basic structure or equality code treating EWS as separate class would be a reasonable classification. Just as equals as unequals, unequals cannot be treated equally.
- न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला ने न्यायमूर्ति त्रिवेदी के साथ सहमति व्यक्त की।
- Justice JB Pardiwala concurred with Justice Trivedi.

EWS Reservation

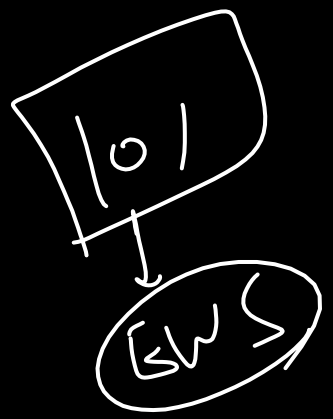

- न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट ने यह कहते हुए असहमति जताने का फैसला किया कि कानून भेदभावपूर्ण है और संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है।
- Justice S Ravindra Bhat decided to dissent, saying the law is discriminatory and violates the basic structure of the Constitution.
- भारत के मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित ने न्यायमूर्ति भट के साथ सहमति व्यक्त की।
- Chief Justice of India U U Lalit concurred with Justice Bhat.

EWS Reservation

Background

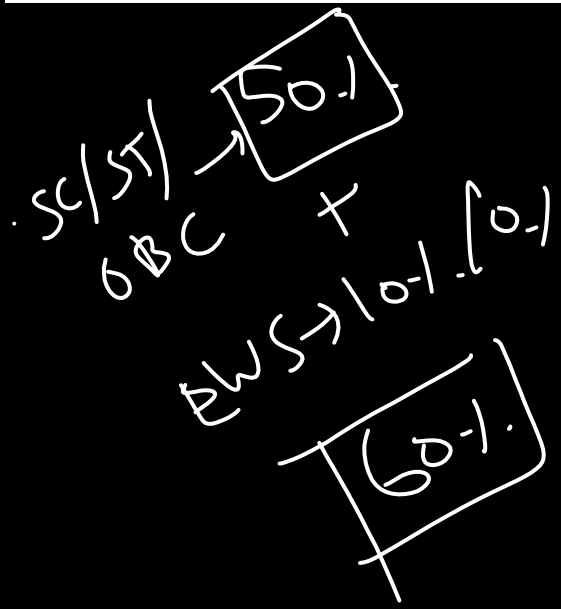

- 7 जनवरी 2019 को, केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण को मंजूरी दी। कैबिनेट ने फैसला किया कि यह एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणियों के लिए मौजूदा 50% आरक्षण से अधिक होगा।

- On 7 January 2019, Union Council of Ministers approved a 10% reservation in government jobs and educational institutions for the Economically Weaker Section (EWS) in the General category. The cabinet decided that this would be over and above the existing 50% reservation for SC/ST/OBC categories.

EWS Reservation

Background

- 10% ईडब्ल्यूएस कोटा 103वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके पेश किया गया था।

- The 10% EWS quota was introduced under the 103rd Constitution (Amendment) Act, 2019 by amending Articles 15 and 16.
- इसमें अनुच्छेद 15 (6) और अनुच्छेद 16 (6) डाला गया।
- It inserted Article 15 (6) and Article 16 (6).

EWS Reservation

- यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए शिक्षा संस्थानों में नौकरियों और प्रवेश में आर्थिक आरक्षण के लिए है।
- It is for **economic reservation** in jobs and admissions in education institutes for **Economically Weaker Sections (EWS).**
- यह अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के लिए 50% आरक्षण नीति के दायरे में नहीं आने वाले गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- It was enacted to promote the welfare of the poor not covered by the 50% reservation policy for Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs) and Socially and Educationally Backward Classes (SEBC).

EWS Reservation

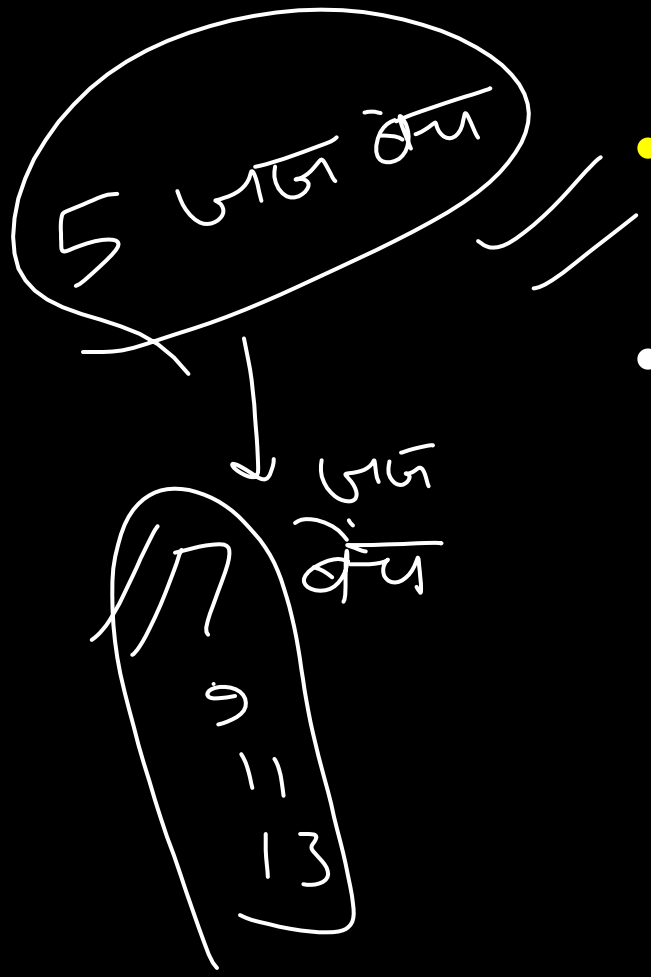

- यह केंद्र और राज्यों दोनों को समाज के ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
- It enables both **Centre and the states** to provide reservation to the **EWS of society.**

103 वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019